www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित
देश की उपासना
देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए
DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर
वर्ष – 04 | अंक – 111 | जौनपुर शुक्रवार, 05 दिसम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान के लिए केरल के कर्मचारियों को छुट्टी दें नियोक्ता : डीके शिवकुमार

कर्नाटक, (एजेंसी)। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को राज्य भर के नियोक्ताओं से अनुरोध किया कि वे केरल के कर्मचारियों को सवेतन अवकाश प्रदान करें, ताकि वे अपने गृह राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान के लिए जा सकें। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नौ और 11 दिसंबर को मतदान होना है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष शिवकुमार ने कहा कि बड़ी संख्या में केरल निवासी बेंगलुरु और कर्नाटक के अन्य हिस्सों में रहते व काम करते हैं। उन्होंने सभी कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, होटलों, ठेकेदारों, बिल्डरों, दुकान मालिकों और अन्य व्यवसाय संचालकों से आग्रह किया कि वे पात्र मतदाताओं को न्यूनतम तीन दिन का सवेतन अवकाश प्रदान करें।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया

असम, (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 20 दिसंबर से प्रस्तावित राज्य की दो दिवसीय यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार को गुवाहाटी में एक बैठक की अध्यक्षता की। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान राज्य में 'विकास की एक नयी लहर' ले आएंगे। मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "असम 20 दिसंबर को नरेन्द्र मोदी का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि वह राज्य में विकास की एक नयी लहर ले आएंगे।" शर्मा ने कहा, "उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत और यात्रा के दौरान होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया।

विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र के खिलाफ विरोध किया प्रदर्शन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली–एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को संसद परिसर स्थित मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सांसद ऑक्सीजन मास्क पहने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करने वाले एक बैनर पकड़े हुए दिखाई दिए, जिस पर लिखा था, मौसम का मजा लीजिए। बैनर पर यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में दिए गए संबोधन के बाद की गई है, जिसमें उन्होंने यह बात कही थी। नारे लगाते हुए, नेताओं ने वायु प्रदूषण पर संसद में चर्चा की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं। इससे पहले आज, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रदूषण को लेकर सरकार की।

नीतीश ने विधानसभा में बिहार के विकास का किया दावा, पीएम मोदी के सहयोग के लिए किया नमन

पटना, (एजेंसी)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में प्रदेश में एनडीए सरकार में किए गए कार्यों का ब्यौरा और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा रखते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में काफी कार्य किए गए हैं। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने इसके लिए सभी सदस्यों को हाथ उठाकर पीएम मोदी को नमन करने का आग्रह किया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने ऐसा ही किया, लेकिन विपक्ष शांत रहा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, ष्बिहार में

सबके लिए काम किया है, आपके लिए भी काम किया है। सब लोग नमन कीजिए।ष मुख्यमंत्री ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि बिहार की जनता ने हालिया विधानसभा चुनाव में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया और एनडीए को भारी बहुमत से विजय दिलाई। उन्होंने इसके लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह विजय सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि बिहार में विकास, शांति और भाईचारे की जीत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार ने भी बड़ा सहयोग किया है। केंद्रीय बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोशी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। उन्होंने पिछले 20 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, महिला सशक्तीकरण क्षेत्र में किए गए कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में विकास को लेकर कहा कि 2008 में कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है।

विकसित भारत के लिए हर भारतवासी मिलकर करें काम : योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2047 में विकसित भारत के लिए हर भारतवासी को साथ मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप पंचप्रण से यह संभव होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन सत्र को बतौर कार्यक्रम अध्यक्ष संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने 37 मिनट के संबोधान के दौरान कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहा है। छह वर्ष बाद शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जाएगा। यह 100 वर्षों के यात्रा के आत्ममंथन का भी समय है। आज परिषद, अपने संस्थापकों के सपनों को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। शताब्दी वर्ष के लिए अभी से लक्ष्य तैयार कर जुट जाएं। सीएम योगी ने कहा कि समाज और राष्ट्र के प्रति हमने अपनी भूमिका का निर्वहन किस तरह किया, है, यह समारोह उसका प्रमाण है। मुख्यमंत्री योगी ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष रहे प्रो. यूपी सिंह को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 2000 साल पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में 46 फीसदी हिस्सा भारत का मुख्यमंत्री ने कहा कि 2000 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था बहुत हीमजबूत थी। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 46 फीसदी। 400 साल पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 26 फीसदी था। देश आजाद हुआ तो डेढ़ प्रतिशत रह गया था। अंग्रेज और विदेशी आक्रांता उस समय

32–33 ट्रिलियन डॉलर लूटकर ले गए थे। आज भारत की अर्थव्यवस्था चार ट्रिलियन डॉलर है। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश है यह पूरी दुनिया ने माना है।

संसद शीतकालीन सत्र 2025 का चौथा दिन, भारत आने वाले समय में उर्जा का निर्यातक होगा : गडकरी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथ दिन है. दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई. लोकसभा में प्रश्नकाल संपन्न हुआ और शून्यकाल चल रहा है. संसद की कार्यवाही अब सुचारू रूप से चल रही है. सत्ता और विपक्ष के बीच एसआईआर को लेकर जारी गतिरोध दूर हो गया है. रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल,

2025 को विचार और पास करने के लिए पेश कर सकती हैं. इस बिल का मकसद नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए रिसोर्स बढ़ाना है और खास सामान बनाने या प्रोडक्शन के लिए लगाई गई मशीनों और दूसरे प्रोसेस पर और उससे जुड़े मामलों के लिए सेस लगाना है। यूपी से सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने लोगों के गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजे जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने पूछा कि कौन सी ऐसी संस्था जो इन लोगों को गलत तरीके से भेजते हैं. सरकार ने इन संस्थाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि एनआईए ने ऐसी संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की है. । दिल्ली –एससीआर में वायु प्रदूषण पर राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा, यह सच है कि प्रदूषण है, लेकिन यह आज या कुछ दिनों का नहीं है, बल्कि यह कई सालों से चल रहा है. सरकार इसे लेकर सीरियस है और इस पर काम भी कर रही है. इतनी बड़ी समस्या को एक बार में हल नहीं किया जा सकता, लगातार कोशिशों की जरूरत होगी. मुझे उम्मीद है कि अगले साल इस पर कुछ ठोस काम होगा और प्रदूषण कम होगा।

समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वालों को सलाम करता है भारत : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को नौसेना दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना के कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि साहस, सतर्कता और अटूट प्रतिबद्धता के साथ हमारी समुद्री सीमाओं और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने वाले बहादुर पुरुषों और महिलाओं कोराष्ट्र सलाम करता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि व्यापार मार्गों की सुरक्षा, समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से लेकर मानवीय मिशनों का नेतृत्व करने तक भारतीय नौसेना अनुशासन, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को दर्शाती है। नौसेना दिवस देश की रक्षा में नौसेना की

महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। नौसेना दिवस के लिए चार दिसंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि यह 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नौसेना के पराक्रम की याद दिलाता है, जब नौसेना ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई! राष्ट्र साहस, सतर्कता और अटूट प्रतिबद्धता के साथ हमारी समुद्री सीमाओं और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने वाले बहादुर पुरुषों और महिलाओं को सलाम करता है। नौसेना दिवस देश की रक्षा में नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। नौसेना दिवस के लिए चार दिसंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि यह 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नौसेना के पराक्रम की याद दिलाता है, जब नौसेना ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, ष्नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई! राष्ट्र साहस, सतर्कता और अटूट प्रतिबद्धता के साथ हमारी समुद्री सीमाओं और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने वाले बहादुर पुरुषों और महिलाओं को सलाम करता है।"

पीएम मोदी ने नौसेना की शान में पढ़े कसीदे, समुद्री सीमाओं की बताई अहमियत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नौसेना दिवस के अवसर पर सभी भारतीय नौसेना कर्मियों को बधाई दी और नौसेना की बढ़ती आत्मनिर्भरता, दृढ़ संकल्प और देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के साहस की सराहना की। भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और राष्ट्रीय सुरक्षा में इसके योगदान के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1971 के युद्ध में नौसेना की सफलता का प्रतीक है, जब ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय सेना ने पीएनएस खैबर सहित चार पाकिस्तानी जहाजों को डुबोकर पाकिस्तानी नौसेना को करारा झटका दिया था। एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना के सभी कर्मियों को

नौसेना दिवस की शुभकामनाएँ। हमारी नौसेना असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का पर्याय है। वे हमारे तटों की रक्षा करते हैं और हमारे समुद्री हितों को बनाए रखते हैं। हाल के वर्षों में, हमारी नौसेना ने आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस साल की दिवाली की यादें उन्हें हमेशा याद रहेंगी, जो उन्होंने स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ बिताई थीं। उन्होंने कहा, ''भारतीय नौसेना को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।'' एक वीडियो संदेश में, प्रधानमंत्री ने देश की समुद्री सीमाओं और आर्थिक जीवनरेखाओं की सुरक्षा में नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि समुद्र में, हमारी नौसेना देश की समुद्री सीमाओं और वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे वह अपतटीय पेट्रोल पोत हों, पनडुब्बी हों या विमानवाहक पोत। आज, भारतीय नौसेना की ताकत तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने वैश्विक भलाई के लिए शक्ति का उपयोग करने की भारत की दीर्घकालिक परंपरा पर जोर देते हुए कहा कि भारत की परंपरा शक्ति और सामर्थ्य की रही है। हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति और हमारी ताकत मानवता की सेवा और मानवता की सुरक्षा के लिए है। आज, जब देश की आर्थिक व्यवस्था परस्पर जुड़ी दुनिया और प्रगतिशील समुद्री सीमाओं पर निर्भर है, भारत की नौसेना वैश्विक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

दिल्ली संचार साथी ऐप नागरिकों की निजता पर खुला हमला : सुरजेवाला

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सरकार ने स्मार्टफोन बनाने वालों के लिए साइबर–सेफ्टी ऐप, संचार साथी, को प्रीलोड करना जरूरी करने वाला ऑर्डर रद्द कर दिया है, लेकिन राज्यसभा में इस पर चिंता जताई गई। कांग्रेस डच रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को राज्यसभा में संचार साथी मोबाइल एप्लिकेशन से जुड़ी चिंताएं जताईं और कहा कि यह नागरिकों की प्राइवेसी के बुनियादी अधिकार पर खुला हमला है। डच ने कहा कि यह हर स्मार्टफोनध्सेल फोन यूजर की प्राइवेसी का साफ उल्लंघन है, जहां ऐप को जरूरी तौर पर इंस्टॉल किया जाएगा या सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, ष्एक साफ आशंका यह है कि ऐप के फीचर्स यूजर की रियल–टाइम जियो–लोकेशन बताने, सेलफोनध्स्मार्टफोन के जरिए की गई सर्च हिस्ट्री और ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग करने और बातचीत मैसेज की पॉसिबल मॉनिटरिंग करने के अलावा, मालिक की सहमति के बिना फोन से सेंसिटिव डेटा इकट्ठा करने की इजाजत देंगे।ष सुरजेवाला ने कहा

कि डर यह था कि ऐप में एक बैकडोर हो सकता है, जिससे यूजर का डेटा और प्राइवेसी पूरी तरह से खतरे में पड़ सकती है, साथ ही फोन में स्टोर पासवर्ड, बैंक अकाउंट नंबर या दूसरी पर्सनल जानकारी जैसी सभी जानकारी भी मिल सकती है। उन्होंने कहा, "अगर ऐप में कोई छोटी सी भी कमी है, तो इससे प्रिविलेज बढ़ सकता है, जिससे हैकर्स को डिवाइस का पूरा कंट्रोल मिल सकता है। इसके जबरदस्ती सिस्टम इंटीग्रेशन का मतलब यह भी है कि पैच व्ड फर्मवेयर अपडेट पर निर्भर करते हैं,।

राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर टिकीं सबकी निगाहें

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भाजपा ने नए अध्यक्ष को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव (संगठन) बीएल संतोष की बुधवार को संसद भवन में हुई बैठक ने नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा फिर से तेज कर दी। बताया जा रहा है कि बंद कमरे में लगभग एक घंटे तक चली इस चर्चा में महत्वपूर्ण संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, बैठक में अगले भाजपा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया, उत्तर प्रदेश के लिए

नए अध्यक्ष का चयन और केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि भाजपा जनवरी तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की तैयारी कर रही है। इससे पहले सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ स्थित आवास पर भाजपा और आरएसएस के बीच समन्वय बैठक हुई। तीन घंटे चली इस बैठक में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि पार्टी इसी हफ्ते नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। नड्डा 2020 से पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्हें 2023 में विस्तार दिया गया था। पार्टी संविधान के अनुसार, अध्यक्ष का चुनाव औपचारिक रूप से होता है, लेकिन स्थापित परंपरा यह है कि सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुना जाता है, जो फिर निर्विरोध श्निर्वाचितश होता है। पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया था कि 14 जनवरी के बाद चुनाव प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है।

प्रतिभा पर रोक लगाने वाले देश भविष्य में घाटे में रहेंगे : एस जयशंकर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पेशेवरों के सीमा पार प्रवाह में बहुत अधिक बाधाएं पैदा करने वाले देश भविष्य में कुल मिलाकर घाटे में रहेंगे। उन्होंने कहा, भारत को अन्य देशों को यह विश्वास दिलाना होगा कि प्रतिभा का उपयोग पारस्परिक लाभ के लिए है। गतिशीलता पर आयोजित सम्मेलन, इंडियाज वर्ल्ड एनुअल कॉन्क्लेव –2025 में उन्होंने यह बात कही। विदेश मंत्री की यह टिप्पणी ट्रंप प्रशासन की ओर से आव्रजन पर की गई कार्रवाई और एच–1बी वीजा पर नए शुल्क लगाने के फैसले से उपजी चिंताओं की पृष्ठभूमि में आई। जयशंकर ने कहा, अगर वे प्रतिभा के प्रवाह में बहुत अधिक बाधाएं खड़ी करते हैं तो वे कुल मिलाकर घाटे में होंगे। खासकर अगर आप उन्नत विनिर्माण के युग में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको अधि

क प्रतिभा की आवश्यकता होगी। विदेश मंत्री एच–1बी वीजा कार्यक्रम से जुड़ी चिंताओं सहित आव्रजन से जुड़े बड़े मुद्दों पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

किसी देश का नाम लिए बिना जयशंकर ने कहा, भारत को अन्य देशों को यह विश्वास दिलाना होगा कि सीमाओं के पार प्रतिभा का उपयोग हमारे पारस्परिक लाभ के लिए है। जयशंकर ने कहा हम दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा हैं और जब आप युवा कामकाजी आयु वर्ग की आबादी को देखते हैं, तो हम एक निश्चित जनसांख्यिकी के वैश्विक कार्यबल का लगभग एक–चौथाई हिस्सा हैं। इसलिए, वैश्विक प्रतिभा–कौशल बाजार में हमारी प्रासंगिकता और बढ़ेगी। विदेश मंत्री ने भारतीय प्रतिभाओं के प्रवाह के मोर्चे पर पिछले दस वर्षों में हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पासपोर्ट सेवाओं के विस्तार से लेकर विदेशों में भारतीयों के लिए कल्याणकारी निधि तक, कैसे भारतीय जनसांख्यिकी आगे बढ़ रही है और दुनिया की जरूरतों को पूरा कर रही है। विदेश मंत्री ने कहा, दस साल पहले, अगर आपको पासपोर्ट चाहिए होता, तो मुझे लगता है कि भारत में 77 जगहें थीं जहां आप जा सकते थे। पिछले दस वर्षों में, हमने ऐसी 468 और जगहें जोड़ी हैं। तो यह पासपोर्ट का विस्तार है, क्योंकि पासपोर्ट ही वह जगह है जहां से आपकी अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता शुरू होती है। जयशंकर ने यह भी बताया कि सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीयों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कैसे कर रही है। उन्होंने कहा, पिछले तीन वर्षों में, केवल खाड़ी देशों में ही, हमने मदद पोर्टल का उपयोग करके 1,38,000 शिकायतों का समाधान किया है।

संपादकीय

जी–20 की प्रासंगिकता काफी घट चुकी

जी–20 की सार्थकता पर प्रश्नचिह्न लगातार गहरा रहे हैं। इस मंच के साझा वक्तव्य हर गुजरते वर्ष के साथ अपना वजन गंवाते चले गए हैं। ट्रंप काल में अमेरिका के बदले नजरिए ने इस प्रक्रिया को और तेजी दे दी है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए जी–20 शिखर सम्मेलन से संकेत देने की कोशिश हुई कि अमेरिका के बिना भी दुनिया चल सकती है। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत समुदाय पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस समिट का बहिष्कार किया। उसी क्रम में उसने दो टूक कहा कि इस सम्मेलन में कोई साझा वक्तव्य जारी नहीं होना चाहिए। फिर भी बाकी सदस्य देशों के प्रतिनिधि ना सिर्फ जोहान्सबर्ग गए, बल्कि उन्होंने साझा वक्तव्य भी जारी किया। उधर दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिका के जूनियर प्रतिनिधि को अगले वर्ष की मेजबानी सौंपने से इनकार कर दिया। कहा कि यह औपचारिकता कम–से–कम विदेश मंत्री स्तर पर निभाई जाएगी। बहरहाल, जोहान्सबर्ग में जो हुआ, उसका प्रतीकात्मक महत्त्व ही है। वरना, एक तो जी–20 की प्रासंगिकता काफी घट चुकी है, दूसरे अमेरिकी उपस्थिति के बिना इसका रहा–सहा महत्त्व भी संदिग्ध हो जाता है। शिखर सम्मेलन स्तर पर जी–20 का आयोजन 2008 की महामंदी के बाद शुरू हुआ था। तब मकसद साझा प्रयास से विश्व अर्थव्यवस्था को संभालना था। तब दुनिया एक ध्रुवीय थी, जिसके तहत लागू श्रम विभाजन में अमेरिका स्थित संस्थाओं ने विभिन्न देशों की भूमिका तय कर रखी थी। मगर उस मंदी ने तत्कालीन समीकरणों को स्थायी रूप से बदल दिया। धीरे–धीरे बनती गई बहु–ध्रुवीय दुनिया में जी–20 के मंच पर आम सहमति बनाना कठिन होता गया है। यूक्रेन युद्ध, अमेरिका– चीन के बीच बढ़े टकराव, गजा में मानव–संहार, और विभिन्न क्षेत्रों में उभरे हॉट–स्पॉट्स के सिलसिले में यह मंच कोई सार्थक भूमिका नहीं निभा पाया है। ट्रंप काल में अमेरिका के बदले नजरिए से ऐसे बहुपक्षीय मंचों की सार्थकता पर प्रश्नचिह्न और गहरे हो गए हैं। यही कारण है कि जी–20 के साझा वक्तव्य हर गुजरते वर्ष के साथ अपना वजन गंवाते जा रहे हैं। यह सिलसिला जोहान्सबर्ग में और आगे बढ़ा। अगले वर्ष मयामी में जब अमेरिका इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तब भी कहानी इससे बहुत अलग नहीं होगी। ट्रंप काल में अमेरिका अपनी विश्व भूमिका को आमूल रूप से बदल रहा है। उसमें जी–20 जैसे मंच उसे सहायक नहीं लगते, तो इस हकीकत को समझा जा सकता है।

फिर से एकता के प्रयास में ममता

अजीत द्विवेदी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर विपक्षी एकता बनवाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इसके लिए प्रयास किया था लेकिन कामयाब नहीं हो पाई थीं। तब के चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल ने भी प्रयास किया लेकिन उनको भी कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी मिली थी नीतीश कुमार को, जो उस समय राजद और कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे थे। उनकी पहल पर विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक पटना में उनके सरकारी आवास एक, अणे मार्ग में हुई थी और बाद में इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ। लेकिन संयोग है कि नीतीश कुमार के इंडिया ब्लॉक छोड़ने का तात्कालिक कारण भी ममता बनर्जी बनीं। असल में राहुल गांधी ने घटक दलों की वर्चुअल मीटिंग में कह दिया था कि नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक का संयोजक बनाने के लिए ममता बनर्जी से पूछना होगा। उस समय तक अलग होने का मन बना चुके नीतीश कुमार को इससे मौका मिल गया और वे वापस भाजपा के साथ लौट गए। अगर नीतीश जनवरी 2024 में भाजपा के साथ नहीं गए होते तो लोकसभा चुनाव की तस्वीर कुछ और होती। बहरहाल, ममता बनर्जी फिर से प्रयास कर रही हैं। इस बार उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का मुद्दा बनाया है। वे चाहती हैं कि सभी पार्टियां मिल कर एसआईआर के खिलाफ साझा आंदोलन चलाएं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतर कर लड़ रही हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस इस लड़ाई में उनका साथ नहीं दे रही हैं। सवाल है कि राहुल गांधी इस बार क्यों नहीं एसआईआर की लड़ाई लड़ रहे हैं? यह सही है कि अभी उनकी पार्टी बंगाल में ममता बनर्जी के साथ नहीं जा सकती है लेकिन कांग्रेस अकेले तो यह लड़ाई लड़ ही सकती है। लेकिन न अकेले लड़ रही है और न ममता के साथ जा रही है। यही विपक्षी एकता के रास्ते में एक पेंच है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में एक साथ मिल कर आंदोलन नहीं करेंगे क्योंकि दोनों को अलग अलग चुनाव लड़ना है। जब दोनों पार्टियां बंगाल में साथ नहीं आएंगी तो फिर एकता कैसे बनेगी? ध्यान रहे यह लोकसभा का चुनाव नहीं है कि ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर एकता बना लेंगी और बंगाल में सबको छोड़ कर अकेले लड़ेंगी। इस बार बंगाल में एकता बनानी और दिखानी होगी, जो कि वे नहीं चाहती हैं। वे सिद्धांत रूप से एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के एक साथ आने की अपील कर रही हैं। यानी समूचा विपक्ष एक साथ होकर एसआईआर के खिलाफ राजनीतिक, कानूनी और संसदीय लड़ाई लड़े और उसके बाद चुनाव में सब अलग अलग लड़ें। इससे जाहिर है कि यह इंडिया ब्लॉक को फिर से रिवाइव करने की योजना का हिस्सा नहीं है, बल्कि तात्कालिक और मुद्दा आधारित एकजुटता का प्रयास है। इस प्रयास में आंशिक कामयाबी ही हासिल होगी। अगले हफ्ते एक दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उसमें सभी पार्टियां एसआईआर का मुद्दा उठा देंगी। उसमें भी कानूनी से ज्यादा मानवीय मुद्दा हावी होगा और सबका जोर इस बात पर होगा कि समय कम होने की वजह से बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ के ऊपर अत्यधिक दबाव है, जिससे उनकी मौत हो रही है या वे खुदकुशी कर रहे हैं। सो, यह तय मानें कि संसद का शीतकालीन सत्र एसआईआर पर हंगामे की भेंट चढ़ेगा। लेकिन वह विपक्षी एकता की गारंटी नहीं है। ध्यान रहे संसद सत्र में लगभग हर बार विपक्ष साथ मिल कर ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है। ममता बनर्जी की अपील अपनी जगह है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी क्यों इस बार एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन या आंदोलन से दूर हैं? बिहार में इस साल जून में जब प्रयोग के तौर पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो सबसे ज्यादा विरोध राहुल गांधी ने किया। उन्होंने इसे वोट चोरी से जोड़ा और बिहार में यात्रा करने पहुंचे। उन्होंने दो हफ्ते तक वोटर अधिकार यात्रा की, जिसमें बिहार की तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए। क्या बिहार के प्रयोग और अनुभव से राहुल गांधी ने समझ लिया है कि एसआईआर कोई चुनावी या बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं है और इसलिए वे दूर हो गए हैं या कोई और कारण है? ध्यान रहे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी राजद के नेता तेजस्वी यादव ने राहुल को समझाया था कि एसआईआर तो ठीक है लेकिन बिहार के स्थानीय मुद्दे गरीबी, बेरोजगारी, पलायन आदि पर बात होनी चाहिए।

पुतिन की भारत यात्रा नयी विश्व राजनीति की आहट

ललित

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा एक साधारण कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि इतिहास के सात दशकों में बुनी एवं गढ़ी गई मित्रता का नवीन उद्घोष है। कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी मित्र और शत्रु नहीं, स्थायी हित होते हैं, किंतु भारत–रूस संबंध इस कथन की परिधि से आगे जाकर स्थायी भरोसे, नैतिक दायित्व और पारस्परिक सम्मान के प्रतीक बने हुए हैं। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका, यूरोप एवं नाटो गठबंधन रूस पर कठोर आर्थिक और रणनीतिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसके बावजूद भारत ने रूस को न केवल कूटनीतिक स्तर पर सम्मान–साथ दिया बल्कि ऊर्जा व रक्षा क्षेत्र में उसे सबसे भरोसेमंद साझेदार माना। इसलिए यह वार्ता केवल दो नेताओं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुलाकात नहीं, बल्कि एक नए युग के सूत्रपात का संकेत है, नयी विश्व राजनीति समीकरण की आहट है। भारत और रूस की मित्रता का इतिहास लगभग 70 वर्षों का है। शीतयुद्ध काल में रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से लेकर पोखरण परमाणु परीक्षणों तक, रूस ने भारत का साथ दिया। आज जब यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक राजनीति को ध्रुवीकृत कर दिया है, अमेरिका ने भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव बनाया, किंतु भारत ने सामरिक स्वायत्तता की नीति को बनाए रखते हुए रूस का साथ निभाया। पश्चिम के प्रतिबंधों के बीच भारत ने भारी मात्रा में रूसी पेट्रोलियम और गैस खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की तथा रूस को आर्थिक सहारा दिया। यह निर्णय महज एक वाणिज्यिक लाभ का मामला नहीं था, बल्कि भारतीय विदेश नीति की स्वयंभूता का प्रदर्शन था। दूसरी ओर, रूस ने भी भारत को कभी निराश नहीं किया। चाहे एस–400 वायु रक्षा प्रणाली हो, टी–90 टैंक हों, ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना हो या पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखू–57 से जुड़ा सहयोग, भारत की सैन्य क्षमता में रूस का योगदान निर्णायक रहा है। वहीं पाकिस्तान की शत्रुता के खिलाफ भारत के हितों को रूस का अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता रहा। हाल ही में दक्षिण एशिया की बदलती सुरक्षा परिस्थितियों में रूस ने भारत की सामरिक चिंता को समझा और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे अभियानों में सहयोग की भूमिका निभाई। यह तथ्य भारत–रूस संबंधों की गहराई और विश्वास को दर्शाता है। पुतिन और मोदी की वार्ता ऐसे समय आयोजित हो रही है, जब वैश्विक शक्ति–संतुलन परिवर्तन के दौर में है। अमेरिका–चीन तनाव, यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी प्रतिबंध, ऊर्जा बाजारों की अस्थिरता और पश्चिमी देशों की रूस के विरुद्ध एकजुटता, इन परिस्थितियों में भारत की भूमिका मध्यस्थ, संतुलक तथा स्वतंत्र धुरी के रूप में उभर रही है। पुतिन भारत को न केवल रक्षा सहयोगी मानते हैं, बल्कि एशियाई भू–राजनीति में संतुलन का स्तंभ भी। वहीं मोदी की विदेश नीति बहुध्रुवीय विश्व की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें रूस का स्थान केंद्रीय है। इस यात्रा से ऊर्जा सहयोग और बढ़ेगा। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और रूस उसके लिए सस्ता, विश्वसनीय तथा दीर्घकालिक आपूर्तिकर्ता। प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने भारत को कच्चे तेल के साथ ही कोयला, गैस और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग दिया। भारत को सस्ती ऊर्जा देने के पीछे केवल व्यावसायिक हित नहीं बल्कि मित्रता और सामरिक साझेदारी भी निहित है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग और विस्तृत होने की उम्मीद है। भारत का लक्ष्य 'मेक इन इंडिया' रक्षा उत्पादन है और रूस इसके लिए सबसे बड़ा भागीदार बना हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल, राइफल निर्माण, स्पेयर पार्ट सप्लाई और संयुक्त विकास कार्यक्रमों के नए विकल्प वार्ता में उभरेंगे। रूस भारत को केवल उपभोक्ता नहीं, निर्माता के रूप में स्थापित करने में सहभागी है, जो संबंधों की परिपक्वता को दर्शाता है। भारत–रूस दोस्ती अब एक नया अध्याय लिखने को तत्पर है। दोनों देशों की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, यहां तक की अमेरिका के साथ बेहतर हुए संबंधों के दौर में भी रूस हमारा विश्वस्त साझीदार बना रहा है, प्रगाढ़ दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से दोनों देशों की दोस्ती में नई गरमाहट की संभावना के साथ दोस्ती के नये स्वस्तिक उकेरने की

बात सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के वर्षों में अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, लेकिन रूस के साथ देश के दशकों पुराने रक्षा संबंध भी बरकरार हैं। भारत ने अमेरिका और यूरोप से हथियारों की खरीद बढ़ाकर रूस पर निर्भरता को संतुलित बनाया है, लेकिन मॉस्को अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। रूस दोस्ती की ओर आगे बढ़ते हुए भारत के लोगों को रोजगार देने के लिये भी एक समझौता मसौदा तैयार किया है। रूस अपने उद्योगों के लिए 10 लाख भारतीय कुशल श्रमिकों को काम पर रखना चाहता है। भारत–रूस संबंधों का सबसे मजबूत आधार है–कूटनीतिक विश्वास और सम्मान। रूस ने कभी भारतीय आंतरिक राजनीति या नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। उसने कश्मीर, परमाणु नीति, रणनीतिक साझेदारी और पड़ोसी विवादों पर भारत की संप्रभुता का समर्थन किया। वहीं भारत ने भी रूस की सुरक्षा चिंताओं को समझाकृचाहे नाटो विस्तार का मुद्दा हो या यूक्रेन का संघर्ष। इसलिए भारत ने पश्चिमी दबावों की उपेक्षा करते हुए संवाद और शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की। अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, अनुसंधान और चिकित्सा के क्षेत्र में भी रूस की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में रूस सहयोगी रहा है और भविष्य की यात्री–वाहक मिशनों में भी सहयोग की संभावनाएँ हैं। दोनों देशों की सांस्कृतिक साझेदारी भी विशेष हैरू योग, आयुर्वेद, साहित्य, रूसी नाटकाकला और भारतीय कलाकृसबने एक–दूसरे समाज में स्थान पाया। फिर भी यह संबंध चुनौतियों से खाली नहीं। चीन–रूस साझेदारी और भारत–अमेरिका निकटता के बीच संतुलन बनाए रखना दोनों देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है। रूस चाहता है कि एशिया में भारत संतुलक भूमिका निभाए, वहीं भारत नहीं चाहता कि रूस का झुकाव चीन की ओर अत्यधिक बढ़े। इसी प्रकार रक्षा सहयोग में तकनीक हस्तांतरण, उत्पादन विलंब और आर्थिक भुगतान व्यवस्थाओं पर भी मतभेद रहे हैं। किंतु इन मतभेदों को वार्ता द्वारा समाधान के प्रयास दोनों राष्ट्रों की परिपक्वता को दर्शाते हैं। पुतिन की इस यात्रा का महत्व इसलिए भी है कि यह बताती है कि भारत किसी वैश्विक शक्ति के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर संबंध तय करता है। ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा आत्मनिर्भरता, बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था और एशियाई सामरिक संतुलन की दृष्टि से भारत–रूस साझेदारी अपरिहार्य है। मोदी और पुतिन की मुलाकात इस विश्वास की प्रामाणिकता है कि संबंध केवल शीत युद्ध की स्मृतियों पर नहीं, बल्कि समकालीन हितों और भविष्य की रणनीति पर आधारित हैं। यह यात्रा एक प्रतीक है–स्वतंत्र विदेश नीति, सामरिक साझेदारी और सांस्कृतिक सम्मान की। भारत–रूस संबंध केवल दो राष्ट्रों की निकटता का परिचय नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक विशिष्ट वैकल्पिक शक्ति संरचना का निर्माण है।

निहित स्वार्थों के लिए युवाओं को गुमराह करने के बयान

योगेंद्र

जमीयत उलमा–ए–हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल में एक कार्यक्रम में कहा कि आज मुसलमान रास्ते पर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें कदम–कदम पर नफरतों का सामना करना पड़ता है। मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाते हुए कहा कि किसी देश में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम–फ्री समाज बनाना इंसाफ के बिना नामुमकिन है। मौलाना ने कहा कि दुख की बात है कि पिछले कुछ सालों में खासकर बाबरी मस्जिद और ट्रिपल तलाक जैसे मामलों में फैसलों के बाद यह आम सोच बन गई है कि कोर्ट सरकारी दबाव में काम कर रहे हैं। राजनीतिक दल और मदनी जैसे मौलाना मुसलमानों में अपनी पैठ बनाने और खुद को उनका सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में कहीं न कहीं मुस्लिम युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के लाल किले के पास विस्फोट की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने खुलासा किया था कि जैश–ए–मोहम्मद से जुड़े डॉक्टरों से जुड़े संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल ने 6 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छह स्थानों पर विस्फोटों की योजना बनाई थी। यह वह दिन था जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। विस्फोट के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकवादियों ने बताया था कि यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि वे बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेना चाहते थे। मौलाना मदनी का बयान ऐसे ही युवाओं को प्रेरित कर गुमराह करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले मौलाना मदनी भूल गए कि अदालतों ने ही आतंक के आरोपों से ढेरों बेगुनाहों को बरी किया है। वर्ष 2006 में 12 लोगों को मुंबई बम धमाकों के संबंध में मकोका कोर्ट ने दोषी ठहराया था, लेकिन 18 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि पुलिस द्वारा पेश किए गए 44,500 पन्नों के दस्तावेजों में से कोई भी दोष सिद्ध नहीं कर सका। इसी तरह गुजरात में 2001 में 127 मुस्लिम नागरिकों को एक प्रतिबंधित संगठन से संबंध के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो 19 साल बाद बरी हुए थे। इसके अलावा ऐसे एकल मामलों की कमी नहीं है, जब अदालतों ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई को अपर्याप्त मानते हुए आतंक के आरोपियों को बरी किया। मुस्लिम हितों की बात करने वाले मौलाना मदनी भूल गए कि यह वही सुप्रीम कोर्ट है, जिसने केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड कानून को ज्यों का त्यों लागू करने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई। विशेष रूप से कोर्ट ने वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होने की शर्त और विवादित संपत्तियों के तुरंत वक्फ माने जाने पर रोक लगा दी। यह फैसला याचिकाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और मामले में संतुलन बनाए रखने के लिए एक अंतरिम रोक है। देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को तलाक का कानूनी हक दिलाने वाले सुप्रीम कोर्ट को मौलाना मदनी भूल गए। मनमाने तरीके से तलाक की शिकार महिलाओं को उनका हक दिलाने की पहल किसी भी मौलवी/मौलाना ने कभी नहीं की। अकेले मौलाना मदनी ही नहीं राजनीतिक फायदे के लिए राजनीतिक दलों के नेता भी मुसलमानों के भले के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते रहे हैं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने लाल किले के सामने हुई ब्लास्ट पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू–कश्मीर का गुस्सा अब लाल किले पर दिख रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक व्यक्ति के अपराध की सजा पूरे जम्मू–कश्मीर के लोगों को नहीं दी जा सकती। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि वे इस गंभीर विषय पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात करें क्योंकि राज्य के बाहर रहने वाले कश्मीरी डरे हुए हैं। महबूबा का यह बयान कहीं न कहीं दिल्ली की वारदात को जायज ठहराने का प्रयास है। महबूबा सत्ता पाने के लिए पूर्व में भी ऐसे विवादित बयान देती रही हैं। महबूबा ने कहा था साल 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू–कश्मीर में ध्डर और घुटन का माहौल है। गिरफ्तारियां हो रही हैं और लोगों पर दबाव है इससे पहले जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ऐसा ही बयान दिया, जिससे कहीं न कहीं आतंकवादियों और उनके पनाहगारों के प्रति सहानुभूति छिपी हुई थी। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने दिल्ली में आत्मघाती हमलावर के परिवार के घर को गिराए जाने पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम सिर्फ गुस्सा बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा अगर आतंकवाद ऐसे कामों से रुक जाता, तो यह बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद हाल ही में कम हुआ है, पिकसी का घर उड़ाने की जरूरत के बिनाष्। सुरक्षा तीन नियंत्रित विस्फोट करके दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के कोइल गांव में डॉ. उमर उन नबी के दो मंजिला घर को ध्वस्त कर दिया था। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने गांदरबल जिले में गैर–स्थानीय मजदूरों पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा में एक्स पर अपने पोस्ट में आतंकी शब्द का जिक्र नहीं किया। इसी तरह पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी अपने पोस्ट में आतंकी शब्द से परहेज किया। इस आतंकी हमले में 7 की जान चली गई थी। विपक्षी दलों ने मुस्लिम आतंकी हो या गैंगस्टर, यही प्रयास किया है कि इनके साथ नरमी बरती जाए। जाहिर कारण है मुस्लिम वोट बैंक। विपक्षी दलों को लगता है कि इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने से मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। सत्ता में आने के बाद पंजाब की मान सरकार ने दावा किया था कि तत्कालीन पंजाब सरकार ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को यूपी सरकार से बचाने के लिए 55 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए थे। मुख्तार को आरामतलब जिंदगी देने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं की गई थीं जो कि एक हाईप्रोफाइल को मिलती हैं। इतना ही नहीं तत्कालीन पंजाब सरकार ने भरसक कोशिश की अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश नहीं भेजा जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट के आदेश से अंसारी की वापसी उत्तर प्रदेश हो सकी। इन उदाहरणों से जाहिर है कि राजनीतिक दल वोट बैंक बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उनकी हरकतों से युवा गुमराह ही क्यों न हो जाएं। आश्चर्य की बात यह है कि मदनी जैसे मौलाना हों या फिर राजनीतिक दल यह भूल गए कि ऐसी तमाम हरकतों को देश के मतदाता कई बार नकार चुके हैं।

नेहरू और बाबरी मस्जिद भाजपा का झूठ

विवेक

देश के पहले प्रधानमंत्री पं.नेहरू का खौफ समूची भाजपा पर इस कदर तारी है कि उसे नित नए झूठ अपने बचाव में गढ़ने पड़ते हैं। नेहरू की जीवनशैली, उनकी महिला मित्र, खान–पान की आदतों को लेकर संघ ने खूब झूठ फैलाया, फिर भाजपा ने इस काम को आगे बढ़ाया। सोशल मीडिया आने के बाद इस दुष्प्रचार में और तेजी आई, फिर भी नेहरू के नाम पर कोई दाग भाजपा नहीं लगा पाई। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में घूमते रहते हैं, अपने नाम की माला जपवाते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में बसे जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिटा पाते। पुरानी पीढ़ी के नेताओं की बात छोड़ दें, नयी पीढ़ी के वैश्विक नेता भी नेहरू–गांधी को ही याद करते हैं। कोई सावरकर, गोलवलकर से प्रेरित होने की बात नहीं कहता। यही पीड़ा संघ को सालती है कि उनके प्रातःस्मरणीय पुरुषों के नामलेवा दुनिया में क्यों नहीं हैं। यह डर और पीड़ा तो लाइलाज है, लिहाजा बेसिरपैर की बातों से भाजपा अपना मन बहलाने में लगी है। ऐसी ही एक बेतुकी बात का उदाहरण पेश किया केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। मंगलवार को गुजरात के वडोदरा में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित श्यूनिटी मार्चश् के दौरान राजनाथ सिंह ने दावा किया कि, श्पंडित जवाहरलाल नेहरू अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल करना चाहते थे। यदि किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, तो वह सरदार वल्लभभाई पटेल थे।श राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का उदाहरण देते हुए यह डर और पीड़ा तो लाइलाज है, लिहाजा बेसिरपैर की बातों से भाजपा अपना मन बहलाने में लगी है। ऐसी ही एक बेतुकी बात का उदाहरण पेश किया केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। मंगलवार को गुजरात के वडोदरा में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं

बताया कि पटेल ने इसे सार्वजनिक दान से ही कराया, जिसमें 30 लाख रुपये जुटाए गए, लेकिन कोई सरकारी धन नहीं लगा। इसके बाद नेहरू–पटेल की परंपरा में जबरन नरेन्द्र मोदी को जोड़ने की कोशिश में राजनाथ सिंह ने कहा कि सोमनाथ की तरह, अयोध्या में मौजूदा राम मंदिर का निर्माण भी पूरी तरह जनता के योगदान से हो रहा है। सिंह ने नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक ताकतें पटेल की विरासत को मिटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पुनर्स्थापित किया। जयंती पर आयोजित श्यूनिटी मार्चश् के दौरान राजनाथ सिंह ने दावा किया कि, श्पंडित जवाहरलाल नेहरू अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल करना चाहते थे। यदि किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, तो वह सरदार वल्लभभाई पटेल थे।श राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का उदाहरण देते हुए बताया कि पटेल ने इसे सार्वजनिक दान से ही कराया, जिसमें 30 लाख रुपये जुटाए गए, लेकिन कोई सरकारी धन नहीं लगा। इसके बाद नेहरू–पटेल की परंपरा में जबरन नरेन्द्र मोदी को जोड़ने की कोशिश में राजनाथ सिंह ने कहा कि सोमनाथ की तरह, अयोध्या में मौजूदा राम मंदिर का निर्माण भी पूरी तरह जनता के योगदान से हो रहा है। सिंह ने नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक ताकतें पटेल की विरासत को मिटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पुनर्स्थापित किया। राजनाथ सिंह का यह भाषण न केवल घोर निंदा के योग्य है, बल्कि सिरे से झूठा होने के कारण गहन चिंताजनक भी है। जब देश के शीर्ष पदों पर बैठे लोग झूठे बयान देने लगें तो सत्यमेव जयते के ध्येय वाक्य की रक्षा कैसे होगी। ऐतिहासिक दस्तावेज के मुताबिक बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने कराया था। यह मस्जिद पहले से मौजूद थी और 1947 से 1964 तक नेहरू के कार्यकाल में इसके श्नए निर्माणश का कोई प्रस्ताव या प्रमाण नहीं मिलता। सब जानते हैं कि पं. नेहरू सरकारी धन के दुरुपयोग के सख्त खिलाफ थे। वे खुद अपना खर्च भी बड़ी किफायत से चलाते थे और ऐसे कई प्रसंग हैं, जिनसे पता चलता है कि उनका स्टाफ अक्सर उनसे उनके पैसे ही बचा कर रखता था, क्योंकि वे जरूरतमंदों को दे देते थे और खुद उनके पास फिर पैसे नहीं बचते थे। नेहरू हर तरह की धर्मांधता और सांप्रदायिकता के विरोधी थे। वे धार्मिक आस्था का सार्वजनिक प्रदर्शन करने के भी खिलाफ थे। बल्कि उनके हिसाब से औद्योगिक कारखाने ही आधुनिक भारत के तीर्थ हैं। अगर नेहरू के बाद की तमाम सरकारें इसी सिद्धांत पर चलती तो आज भारत विकास में चीन, जापान, अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों को टक्कर देता। लेकिन धर्म के नाम पर राजनैतिक समझौता करने की नीति ने देश को पीछे ही रखा। नेहरू जैसी दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति उनके बाद के प्रधानमंत्री नहीं दिखा पाए। नेहरू सरकार को धार्मिक कार्यों में संलग्न होने या जनता के धन को धार्मिक स्थलों में इस्तेमाल करने के सख्त खिलाफ थे। इसलिए 1951 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान नेहरू ने सरकारी फंडिंग का विरोध किया था, जिसे पटेल ने सार्वजनिक ट्रस्ट के माध्यम से पूरा कराया था। सरदार पटेल भी नेहरू जैसी ही सिद्धांतवादी थे। उन्होंने कहा था कि जब तक वे जिंदा हैं सोमनाथ मंदिर के लिए सरकारी खजाने से एक पैसा नहीं देंगे। तो भारत के संविधान और नेहरू–पटेल की नीतियों में कोई भेद नहीं था। जबकि आज की सरकार इसके बिल्कुल उलट काम कर रही है। राजनाथ सिंह सोमनाथ मंदिर और राम मंदिर की तुलना कर रहे हैं। और बड़ी आसानी से इस बात की अनदेखी कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बनाया गया है। मंदिर निर्माण में जनता के धन का दावा भी कितना सच है, इसका प्रमाण भाजपा को हिसाब के साथ देना चाहिए। मंदिर के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक और अभी ध्वज फहराने तक मोदी जो बार–बार अयोध्या गए हैं, वो खर्च भी जनता के टैक्स के पैसे पर ही उठाया गया है। बहरहाल, राजनाथ सिंह के दावे पर विरोध शुरु हो चुका है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, श्मुझे बस इस बात से दुख है कि राजनाथ सिंह ऐसा कह रहे हैं, सकता है कि वह अपनी पार्टी से प्रभावित हो गए हों, या उन्हें ऐसी बातें कहने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। नेहरू ने उन्हें (सरदार वल्लभभाई पटेल) उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया था... राजनाथ जी, यह बयान आपके इतिहास या आपके व्यक्तित्व के साथ मेल नहीं खाता...।श इस बयान से ऐसा लग रहा है मानो प्रमोद तिवारी राजनाथ सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनाथ सिंह संघ की सांप्रदायिक राजनीति से प्रभावित हैं, इसलिए ही भाजपा में बने हुए हैं। बल्कि टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने ठीक कहा है कि, श्राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के रूप में एक बहुत ही जिम्मेदार संवैधानिक पद पर हैं। उन्हें या तो अपनी बात के सबूत पेश करने चाहिए।

एनपीएस में छोटी बचत से बड़ी सुरक्षा, सबसे भरोसेमंद आर्थिक सुरक्षा का विकल्प

लखनऊ, (संवाददाता)। सरकारी और कॉर्पोरेट वर्ग के साथ अब किसानों को भी आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में कदम बढ़े हैं। विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के संयुक्त सहयोग से बुधवार को 'बीज एनपीएस का, फसल पेंशन की' विषय पर विशेष वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। वित्तीय विशेषज्ञों ने कहा कि 60 वर्ष पार किसान भी अब आर्थिक चिंता से मुक्त रह सकते हैं, बस उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) अपनाने की जरूरत है। कृष्णानगर स्थित एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ पीएफआरडीए के मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) आशीष कुमार ने कहा कि एनपीएस केवल निवेश नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर वृद्धावस्था की दिशा में एक आंदोलन है। महज 500 रुपये के नियमित निवेश से लोग अपने बुढ़ापे को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं। एनपीएस कैलकुलेटर के जरिये अधिकारियों ने बताया कि एनपीएस औसतन निवेश के 10 गुना तक पेंशन कॉर्पस बनाने की क्षमता रखता है। खेती–किसानी से जुड़े लोग, जिनकी आय मौसम व बाजार पर निर्भर रहती है, उनके लिए यह योजना जीवनभर की स्थायी आय का मजबूत साधन साबित हो सकती है। विशेषज्ञों ने दूरदराज से आए किसानों को समझाया कि छोटी–छोटी रकम के नियमित निवेश से वे वृद्धावस्था में हर महीने सम्मानजनक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान किसानों के सवाल भी लिए गए और उनकी शंकाओं का समाधान किया गया। इस मौके पर नाबार्ड के डीजीएम सिद्धार्थ सरकार, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (एलडीएम) मनीष पाठक, बैंक ऑफ बड़ौदा की डीजीएम एवं एसएलबीसी संयोजक निधि कुमार, ओपन एग्री नेटवर्क 'समउन्नति' के अधिकारी निहिल चावला भी मौजूद रहे। एनपीएस किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समउन्नति अपने 6500 से अधिक एफपीओ और 80 लाख किसानों के नेटवर्क को इस योजना की जानकारी दे रही है। कार्यक्रम में एलडीएम मनीष पाठक और बैंक ऑफ बड़ौदा की डीजीएम ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। वृद्धावस्था में आय का मुख्य सहारा पेंशन होती है। खेती के जोखिम मौसम, कीट, बाजार भाव और बढ़ती लागत किसानों की आमदनी को अस्थिर करते हैं। ऐसे में एनपीएस जीवनभर नियमित पेंशन देने वाला सुरक्षित ढांचा है, जो भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाता है और वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है। जो किसान युवा अवस्था में एनपीएस से जुड़ते हैं, उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे बड़ा लाभ मिलता है। छोटी–छोटी मासिक बचत भी 20–30 वर्षों में एक मजबूत रिटायरमेंट फंड में बदल जाती है। किसानों की अनियमित आय के बावजूद एनपीएस लचीला है, कभी भी, किसी भी राशि से निवेश शुरू किया जा सकता है। अक्सर किसान अपनी वृद्धावस्था में बच्चों या रिश्तेदारों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन बदलते सामाजिक ढांचे और शहरों की ओर बढ़ते पलायन ने इस व्यवस्था को अस्थिर बना दिया है।

अधिवक्ता दिवस पर 18 मेधावी सम्मानित

लखनऊ, (संवाददाता)। अधिवक्ता दिवस पर बुधवार को सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन लखनऊ की ओर से 10वीं व 12वीं के 18 मेधावियों को सम्मानित किया गया। मीराबाई मार्ग स्थित राज्य कर भवन में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजपाल यादव रहे। अधिवक्ता सुमित तिवारी ने होनहार शशिकांत मिश्रा, जयंत गुप्ता, एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मिश्र व लीना मिश्रा ने सोनम सिंह, शिवांश कुमार, जयंतिका गुप्ता, गणेश गुप्ता को सम्मान किया। अनुराग मिश्रा ने दिव्यांशी पांडेय, दीपांश कुमार त्रिवेदी और नृपेंद्र सिंह ने प्रत्यक्षा यादव, सिफ्ती गंभीर, आर्या पांडेय को सम्मानित किया।

संक्षिप्त खबरें

नगर आयुक्त एकादश ने दर्ज की बड़ी जीत

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर आयुक्त एकादश ने प्रेस एकादश को 38 रन से मात देते हुए नगर निगम क्रिकेट प्रतियोगिता में पूरे अंक प्राप्त किए। नगर आयुक्त एकादश के 166 रन के जवाब में प्रेस एकादश की टीम चार विकेट खोकर 128 रन बना सकी। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में नगर आयुक्त एकादश ने टॉस

जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट खोकर 166 रन बनाए। अंकित कुमार और अनिल सिंह ने 40–40 रन की पारी खेली। मयूर शुक्ला और विवेक चौहान ने दो–दो विकेट हासिल किए। जवाब में प्रेस एकादश की टीम चार विकेट खोकर 128 रन बना सकी और मुकाबला 38 रन से गंवा बैठी। इश्तियाक ने नाबाद 47 और मयूर शुक्ला ने 29 रन का योगदान दिया। मनीष, विकास, अनिल और ललित ने एक–एक विकेट लिया।

मॉडर्न अकादमी ने जीता वॉलीबाल का खिताब

लखनऊ, (संवाददाता)। मॉडर्न अकादमी के खिलाड़ियों ने लखनऊ स्कूल गेम्स की वॉलीबाल स्पर्धा में श्रेष्ठता साबित करते हुए स्वर्ण पदक जीता। टीम ने यह सफलता अंडर–14 आयुवर्ग में हासिल की। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मॉडर्न अकादमी ने एलपीएस आनंद नगर को शिकस्त दी। आयोजन समिति अध्यक्ष व संयोजक अनुज कुमार तिवारी ने बताया कि चौक स्टेडियम पर आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता (अंडर–17 बालक वर्ग) में सरस्वती विद्या मंदिर के प्रगेश सिंह ने स्वर्ण, कर्नल एस.एन. मिश्रा ओबीई मेमोरियल स्कूल के अनुज कुशवाहा ने रजत व मॉडर्न अकादमी के शिवांश बरनवाल ने कांस्य पदक जीता। खेलों की बालिका अंडर–17 कबड्डी में सेंट जोसेफ राजाजीपुरम ने स्वर्ण अपने नाम किया। टीम से आसान फाइनल मुकाबले में लखनऊ पब्लिक कॉलेज को पराजित किया।

दिव्यांग बच्चों को किया सम्मानित

लखनऊ, (संवाददाता)। कैसरबाग स्थित गांधी भवन में बुधवार को कीर्ति फाउंडेशन कल्याणपुर की ओर से सामर्थ्य की उड़ान सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें दिव्यांग बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यवसाय में नई पहचान बनाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया।

कर्नल सीमा मिश्रा बनीं सैनिक स्कूल की प्रधानाचार्या

लखनऊ, (संवाददाता)। कर्नल सीमा मिश्रा को कैप्टन मनोज पांडेय उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की प्रधानाचार्य बनाया गया है। इस संबंध में 30 अक्तूबर को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन इंस्पेक्टिंग ऑफिसर सैनिक स्कूल सोसाइटी की ओर से प्रतिनियुक्ति की तय शर्तों के आधार पर पत्र जारी किया गया था। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा अपर मुख्य सचिव की ओर से औपचारिकता पूरी करते हुए आदेश जारी किया गया है। प्रधानाचार्या के पद पर कर्नल सीमा मिश्रा का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। इस दौरान उन्हें नियमानुसार लागू सभी भत्ते व वेतन दिया जाएगा। इससे पहले सीमा पंजाब के कपूरथला सैनिक कॉलेज में तैनात थीं। यूपी सैनिक स्कूल की कमान पहली बार महिला प्रधानाचार्य के हाथ आई है।

केजीएमयू खाली पदों पर अब संविदा डॉक्टरों की करेगा भर्ती

लखनऊ, (संवाददाता)। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में डॉक्टरों के खाली पदों पर संविदा पर भर्ती की जाएगी। नियमित नियुक्ति में लगने वाले लंबे समय को देखते हुए यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियम के अनुसार, सभी क्लीनिकल या सुपर स्पेशियलिटी विभाग में कम से कम एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर तथा एक असिस्टेंट प्रोफेसर होना जरूरी है। इस लिहाज से विभाग में कम से कम तीन शिक्षक जरूर होने चाहिए। इसके बावजूद केजीएमयू में इस समय नेफ्रोलॉजी, न्यूक्लीयर मेडिसिन, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गैस्ट्रो मेडिसिन, पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन समेत कई विभागों में या तो शिक्षक नहीं हैं या फिर मानक से कम हैं। केजीएमयू प्रशासन ने वर्ष 2022 में 150 पदों

पर डॉक्टरों की भर्ती निकाली थी। आरक्षण संबंधी विवाद और अन्य कानूनी अड़चन से करीब दो साल बाद वर्ष 2024 में यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकी। हालांकि, इसमें भी सिर्फ 77 डॉक्टरों का चयन हो सका। इस वजह से अब भी संस्थान में डॉक्टरों की कमी है। इसको देखते हुए केजीएमयू प्रशासन ने संविदा के आधार पर डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। विभागवार डॉक्टरों की भर्ती का ब्योरा अगले दो–तीन दिन में जारी किया जाएगा। केजीएमयू प्रवक्ता प्रो. केके सिंह के मुताबिक, संविदा के आधार पर तैनाती की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके साथ ही नियमित पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

जानवर से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलटी बस

लखनऊ, (संवाददाता)। बहराइच जिले के नानपारा बाईपास पर बृहस्पतिवार तड़के एक निजी बस के जानवर से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि बस में सवार यात्री संभल भी नहीं पाए। इस दुर्घटना में 12 यात्री घायल हुए जिनमें पांच यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा भेजा गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वैशाली एक्सप्रेस नाम की बस संख्या यूपी 43 बीटी 1530 पंजाब से बहराइच होते हुए श्रावस्ती की ओर जा रही थी। बस में करीब 35 यात्री सवार थे, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। जैसे ही बस कोतवाली नानपारा के मलंगपुरवा गांव के पास पहुंची, अचानक सड़क पर

एक जानवर आ गया। चालक बस को संभाल नहीं पाया और वाहन पलटकर सड़क किनारे जा गिरा। हादसे में घायल यात्रियों में सिद्धार्थनगर जिले के गौरा निवासी कुसुम देवी (35) पत्नी महिलाल यादव, बलरामपुर के कोटिया गांव निवासी रचना देवी (40) पत्नी शिवपूजन शर्मा, श्रावस्ती के जौगढ़ निवासी इंद्रजीत मौर्य (28) पुत्र फौजदार मौर्य, सोनारी निवासी गिरधारी कुम्हार (26) पुत्र ननकू कुम्हार और राजेश पाल (39) पुत्र जमुना प्रसाद पाल, निवासी निगोही बहराइच शामिल हैं। प्रभारी निरीक्षक राजनाथ सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल भेजवाया तथा मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कराया। बस पलटने के कारण बाईपास पर यातायात बाधित हो गया था। पुलिस ने हाइड्रा मशीन बुलवाकर बस को हटवाया और करीब दो घंटे बाद सड़क पर यातायात सामान्य हो सका।

संक्षिप्त खबरें

कैरम, टेबल टेनिस में छाए दिव्यांग

लखनऊ, (संवाददाता)। विश्व दिव्यांग दिवस पर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन विभाग में बुधवार को दिव्यांगों के लिए कैरम, टेबल टेनिस समेत कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें सुचिता यादव, अफसर बानी, सरोजा,

सरवर कुमार, स्नेहा, शिवदीप, सरवन, इकरार को पुरस्कार मिला। लिंब सेंटर के वुडेर हॉल में हुए कार्यक्रम में कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने कहा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न अंग हैं। इन्हें समान अधिकार और अवसर दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। पीएमआर विभाग के अध्यक्ष डॉ. अनिल गुप्ता ने कहा, दिव्यांगजनों की क्षमताएं किसी भी सामान्य व्यक्ति से कम नहीं हैं। कुलपति ने दिव्यांगजनों को निशुल्क कृत्रिम व सहायक कृत्रिम अंग वितरित किए। कार्यक्रम में डॉ. अविनाश अग्रवाल, डॉ. अनित परिहार, डॉ. अमिय अग्रवाल, डॉ. दिलीप, डॉ. संदीप गुप्त, प्रदीप गंगवार, शगुन सिंह, शोभाराम, बलराम श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

फॉर्म जमा करने में देरी से बीएलओ, सुपरवाइजर परेशान

लखनऊ, (संवाददाता)। बीएलओ से फॉर्म लेकर जाने के बाद उसे जमा करने में मतदाताओं की ओर से की जा रही देरी से बीएलओ खासे परेशान हैं। आलम यह है कि इसके लिए बीएलओ व सुपरवाइजर क्षेत्र में पहुंचकर अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं। विकास भवन स्थित चिनहट विकास खंड कार्यालय सभागार में एसआईआर को लेकर बुधवार को पूरे दिन बीएलओ व सुपरवाइजर जुटे रहे। इस सभागार में विधानसभा क्षेत्र 173 लखनऊ (पूर्वी) से जुड़े मतदाताओं के एसआईआर का कार्य चल रहा है। इसके लिए 417

बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। सुपरवाइजर दिनेश कुमार व कुछ अन्य सुपरवाइजरों ने बताया कि बीएलओ से फॉर्म लेकर जाने वाले कई मतदाता उसे जमा करने अभी तक नहीं आए हैं। प्रशासन की ओर से वितरित किए गए फॉर्म एकत्र कर उसे फीड करने को कहा जा रहा है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसीएम–चतुर्थ डॉ. सचिन कुमार ने कार्य का जायजा भी लिया।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत ललितपुर में गोवर्धन परियोजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती

लखनऊ, (संवाददाता)। ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश पंचायतीराज विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के अंतर्गत गोवर्धन परियोजना को नई गति दी है। जनपद ललितपुर की ग्राम पंचायत कारीपहाड़ी में 85 घनमीटर क्षमता वाला बायोगैस संयंत्र स्थापित कर पूर्ण रूप से संचालित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण आजीविका, स्वच्छ ऊर्जा और स्थानीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय परिणाम देखने को मिले हैं। यह संयंत्र प्रदेश में एक सफल और प्रेरक मॉडल के रूप में उभर रहा है।संयंत्र से उत्पादित गैस 12 परिवारों को पाइपलाइन के माध्यम से प्रतिदिन सुबह और शाम उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उन्हें स्वच्छ, सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त संयंत्र से उत्पन्न गैस का उपयोग 15 केवीए क्षमता के जेनरेटर के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है, जो दो निर्मित कक्षों में स्थापित आटा चक्की के संचालन में लगाया जा रहा है। कम लागत पर उपलब्ध पिसाई सुविधा के कारण आसपास के गांवों के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं।संयंत्र से लाभान्वित परिवारों से गैस के लिए प्रतिमाह 250 रुपये तथा आटा पिसाई के लिए प्रति किलो 1 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। साथ ही संयंत्र से प्राप्त जैविक खाद (स्लरी) क्षेत्र के कृषि किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे फसलों की उत्पादकता में सुधार के साथ ग्रामीणों को जैविक उर्वरक का विकल्प भी मिल रहा है। इस संयंत्र से प्राप्त आय लगभग 3,05,990 रुपये ग्राम पंचायत के वित्तीय खाते में जमा की जा चुकी है, जिससे पंचायत को वित्तीय स्वावलंबन प्राप्त हो रहा है। संयंत्र संचालन हेतु स्थानीय किसान को केयर–टेकर के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्हें प्रतिमाह 5,000 रुपये मानदेय प्रदान किया जा रहा है।माननीय मंत्री पंचायतीराज, श्री ओमप्रकाश राजभर ने इस परियोजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, स्वच्छता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत कारीपहाड़ी का यह सफल मॉडल पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत है और इसे अधिकाधिक ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा।निदेशक पंचायतीराज, श्री अमित कुमार सिंह ने कहा कि गोवर्धन परियोजना यह सिद्ध करती है कि सही प्रबंधन के माध्यम से अपशिष्ट को ऊर्जा, आजीविका और आय का अत्यंत उपयोगी स्रोत बनाया जा सकता है।

गोमतीनगर में महिला की हत्या का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ (आरएनएस)गोमतीनगर थाना क्षेत्र में मिली एक अज्ञात महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 1 दिसंबर को सामने आई थी, जब अलीगंज निवासी राकेश कुमार ने अपनी बहन रेखा वर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जानकारी पुलिस को दी। तहरीर के आधार पर थाना गोमतीनगर में बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचना उपनिरीक्षक विनोद कुमार सिंह को सौंपी गई।मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्वी जोन के उच्चाधिकारियों ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम को साक्ष्य एकत्र करने के लिए भेजा। पुलिस ने घटनास्थल और आस–पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तथा स्थानीय लोगों से पूछताछ कर संदिग्धों के बारे में महत्वपूर्ण इनपुट जुटाए। क्राइमध्सर्विलांस टीम और गोमतीनगर पुलिस की संयुक्त जांच के बाद घटना में शामिल दोनों आरोपियोंकृदेवेन्द्र सिंह और सूरज पालकृकी शिनाख्त हुई, जिन्हें 3 दिसंबर की सुबह विनीत खंड स्थित सब्जी मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया।पूछताछ में देवेन्द्र ने बताया कि 30 नवंबर की रात वह अपने ई–रिक्शा से नवाबपुरवा स्थित शराब की दुकान पर गया था, जहां एक महिला ने उसे रोककर लिफ्ट मांगी। रास्ते में बातचीत के दौरान दोनों आरोपियों ने उससे शराब पीने और शारीरिक संबंध बनाए जाने की बात कही। शराब पिलाने के बाद दोनों उसे विशाल खंड स्थित झोपड़ी में ले गए, जहां नशे में विवाद होने पर उन्होंने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। महिला का सिर पीछे रखे तख्ते से टकराया और वह बेहोश होकर गिर गई। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद दोनों ने देर रात तीन बजे शव को ई–रिक्शा में डालकर विशाल खंड के पास एक सूनसान गली में छोड़ दिया।

बीबीएयू में नवाचार डिजाइन और उद्यमिता पर द्विदिवसीय कार्यशाला आज से शुरू

लखनऊ, (संवाददाता)। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में 4 दिसंबर से नवाचार डिजाइन और उद्यमिता विषय पर आधारित द्विदिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला की शुरुआत होने जा रही है। यह विशेष कार्यशाला जिला शिक्षा अधिकारियों, क्म्ज् प्रतिनिधियों और ब्म्ज् सदस्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, ताकि विद्यालयी शिक्षा में नवाचार और उद्यमिता की नई संभावनाओं को पहचाना और आगे बढ़ाया जा सके।इस कार्यक्रम का आयोजन बीबीएयू के साथ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय का नवाचार प्रकोष्ठ, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया), स्कूल इनोवेशन काउंसिल तथा वाधवानी फाउंडेशन के संयुक्त सहयोग से किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे, जबकि एडीशनल स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर विष्णु कांत पाण्डेय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नोडल सेंटर हेड प्रो. नवीन कुमार अरोड़ा और कोऑर्डिनेटर डॉ. अर्पित शैलेश भी आयोजन में उपस्थित रहेंगे।कार्यशाला में दो दिनों तक विद्यालयों में नवाचार और उद्यमिता की महत्ता, नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों की दिशा में उठाए जाने वाले कदम, तथा समस्या–समाधान के मानव–केंद्रित दृष्टिकोण यानी डिजाइन थिंकिंग पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रतिभागियों को डिजाइन थिंकिंग की अवधारणा, उसके व्यावहारिक उदाहरणों, केस स्टडीज और समूह कार्य के माध्यम से नवाचार की गहरी समझ विकसित करने का अवसर मिलेगा।इसके साथ ही कार्यक्रम में विद्यालयी संदर्भ में उद्यमिता को बढ़ावा देने, नवाचार पारितंत्र को मजबूत करने तथा स्कूलों को वैश्विक स्तर है।

उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री ने गोआश्रय स्थलों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में प्रदेश के सभी गोआश्रय स्थलों का एक सप्ताह में किए गए निरीक्षण की समीक्षा की और आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए। मंत्री ने अधिकारियों को नियमित रूप से गोशालाओं का निरीक्षण करने, प्रकाश और सोलर लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करने, गोवंश के लिए हरा चारा, ठंड से बचाव, तिरपाल, औषधियां और पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक गोशाला पर सीसीटीवी सक्रिय करने और वृहद गोसंरक्षण केन्द्रों पर ड्रोन उपयोग की संभावनाओं पर विचार करने का भी आदेश दिया।बैठक में मंत्री ने प्रदेश में निराश्रित गोवंश संरक्षण हेतु संचालित गोआश्रय स्थलों के संचालन, प्रबंधन, संरक्षित गोवंश के भरण पोषण, पराली संग्रहण तथा एलएसडी बीमारी के नियंत्रण और दुग्ध समितियों के संचालन की स्थिति की मण्डलवार गहन समीक्षा की। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार जनपद अयोध्या में सभी गोआश्रय स्थलों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं और अधिकांश स्थलों पर पराली संग्रहण किया जा रहा है। बाराबंकी में संरक्षित गोवंश के लिए पर्याप्त भूसा, साइलेज, पशु आहार और हरा चारा उपलब्ध हैं। कासगंज में हरा चारा उपलब्ध है लेकिन साइलेज की कमी है और अस्थायी गोआश्रय स्थल मण्डी समिति में अतिरिक्त शेड की आवश्यकता है। हापुड़ में ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा नियमित भ्रमण नहीं किए जाने के कारण गोवंश को पर्याप्त हरा चारा, दाना और भूसा नहीं मिल रहा है। महराजगंज में सीसीटीवी कैमरे संचालित नहीं हैं। कानपुर देहात में गोवंश को हरा चारा नहीं दिया जा रहा और अभिलेख पूर्ण नहीं हैं। प्रतापगढ़ में पशु आहार का टेंडर नहीं हुआ और गोशालाओं की सफाई संतोषजनक नहीं है।श्री सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जहां भी कमी पाई गई है वहां गोवंश की बेहतर देखभाल और अन्य व्यवस्थाओं को शीघ्र दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि ठंड से किसी भी गोवंश की मृत्यु न हो और पशुचिकित्साधिकारी गोशालाओं में जाकर गोवंश के स्वास्थ्य, चिकित्सा और औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। दुग्ध समितियों का संचालन सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकताओं में है और सभी जिम्मेदार अधिकारी प्रशासनिक स्तर पर गोशालाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करें।मंत्री ने कहा कि योगी सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। गोवंश शेड, खाना और पानी पीने की व्यवस्था मजबूत एवं व्यवस्थित तरीके से की जाए। जिन गोआश्रय स्थलों में अव्यवस्था या गोवंश की देखभाल में कोई कमी हो वहां तुरंत सुधार किया जाए और गुणवत्ता पर पूरा ध्यान रखा जाए।बैठक में प्रमुख सचिव पशुधन एवं दुग्ध विकास मुकेश मेश्राम ने मंत्री को आश्वस्त किया कि गोआश्रय स्थलों पर सभी व्यवस्थाएं निर्देशानुसार सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त रूप से निर्देशित किया कि गोशालाओं में कोई अव्यवस्था न हो और गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं।बैठक में बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश में 7,560 निराश्रित गोआश्रय स्थल हैं, जिनमें 12,35,253 गोवंश संरक्षित हैं। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत कुल सुपुर्द गोवंश 1,80,919 हैं, जिनसे 1,14,628 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। बैठक में पशुधन विभाग के विशेष सचिव देवेन्द्र पाण्डेय, पीसीडीएफ के एमडी वैभव श्रीवास्तव, दुग्ध आयुक्त के0 धनलक्ष्मी, विशेष सचिव दुग्ध राम सहाय यादव, निदेशक (प्रशासन एवं विकास) डॉ. मेमपाल सिंह, सीईओ यूपी एल0डी0बी0 डॉ. पी.एन. सिंह, संयुक्त निदेशक डॉ. पी.के. सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत के लिए अयोध्या धाम में किया गया भव्य उद्घाटन– संत महात्माओं की शुभ भावना एवं आशीर्वाद के साथ हुई शुरुआत

दैनिक देश की उपासना ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम 3 दिसंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 को नशा मुक्त भारत अभियान का उद्घाटन अयोध्या धाम से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ है जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या धाम महंत जनमेजय शरण जी महाराज जी के तत्वाधान में स्थान पर नशा

मुक्ति अभियान के पूज्य संतों महंतों के माध्यम से हुआ जिसमें माउंट आबू हेडक्वार्टर से आए वरिष्ठ राजयोगी डॉक्टर बनारसी लाल भाई मेडिकल मेडिकल विंग जनरल सेक्रेटरी का सम्मान करते हुए शुभकामनाएं दी गई इस अवसर पर नागा राम लखन दास महाराज, कोठारी जी महाराज, रामगोपाल मंदिर के महंत लक्ष्मण किला धीश महाराज, हनुमान किला के महंत परशुराम दास महाराज ,महंत नारायण दास महाराज बावन मंदिर सरकार ब्रह्म कुंड के महंत ज्ञानी गुरजीत सिंह ,बड़े हनुमान मंदिर के छवि रामदास महाराज, रामकोट दशरथ गाड़ी के महंत ब्रिज मोहनदास महाराज ,भरत कुंड के महाराज, कामधेनु मंदिर के महामंडलेश्वर आशुतोष जी महाराज, डांडिया मंदिर के महाबलेश्वर महाराज गिरीश दास जी के साथ–साथ स्थानीय सेवा केंद्र संचालक अयोध्या धाम से बीके मुकेश भाई ,माउंट आबू से बीके चंद्रेश भाई ,जौनपुर से बी के सुनीता बहन, बी के रंजीत भाई, तथा बीजेपी से इंजीनियर रवि तिवारी भाई, विदेश संपर्क विभाग अयोध्या धाम एवं राधेश्याम त्यागी भाई ,भाजपा जिला मंत्री मुकेश तिवारी भाई बीजेपी मंडल अध्यक्ष तथा अनेक संघ प्रचारक के साथ साथ किसान मोर्चा अध्यक्ष भाजपा चंद्रशेखर भाई ,जल पुलिस कार्यकर्ता तथा एलो जोन प्रभारी और काफी संख्या में अनेक संत महंत और अधिकारी गण भी मौजूद रहे, कार्यक्रम में सरयू आरती समिति के अध्यक्ष राजा महाराजा महाराज जी ने डॉक्टर बनारसी भाई एवं समस्त बी के परिवार का सम्मान किया गया और नशा मुक्ति अभियान की कामयाबी के लिए अपनी शुभकामनाएं दी गई।

एसकेडी एकेडमी के छात्रों ने लक्ष्मणपुरी क्रीड़ा महोत्सव में किया शानदार प्रदर्शन

लखनऊ। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एसकेडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के स्कूल, एसकेडी एकेडमी के छात्रों ने हाल ही में आयोजित लक्ष्मणपुरी क्रीड़ा महोत्सव में अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए शानदार सफलता हासिल की है। यह महोत्सव चौक स्टेडियम,

लखनऊ में आयोजित किया गया था। एसकेडी एकेडमी के होनहार खिलाड़ियों ने कई खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया। खो–खो–अंडर–14 (लड़कियों) की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। कबड्डी– अंडर–14 (लड़कों) की टीम ने अपनी ताकत और रणनीति का परिचय देते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। कबड्डी– अंडर–17 (लड़कों) की टीम ने भी प्रतिद्वंद्वी टीमों को कड़ी टक्कर देते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस शानदार उपलब्धि पर, एसकेडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक, श्री मनीष सिंह ने सभी विजेता छात्रों और उनके प्रशिक्षकों को हार्दिक बधाई दी। 'श्री मनीष सिंह ने अपने संदेश में कहा– हमारे छात्रों की यह सफलता यह दर्शाती है कि शिक्षा के साथ–साथ खेल में भी वे किसी से कम नहीं हैं। मैं सभी छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूँ और उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि वे इसी तरह आगे बढ़ते रहें और केवल अपने स्कूल का ही नहीं, बल्कि देश का नाम भी रोशन करें। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। एसकेडी एकेडमी हमेशा से ही छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है और यह जीत इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

सरकार ऐसा आईडी जारी करे, जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो सके कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन घुसपैठिया नहीं है – डॉ. रागिनी सोनकर

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में मछली शहर से सपा विधायक डॉ रागिनी सोनकर ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करने के आदेश पर डॉ. रागिनी सोनकर ने इस प्रक्रिया में निष्पक्षता बरतने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आवश्यक

दस्तावेज नहीं हैं और संबंधित अधिकारी भी उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। विधायक डॉ. सोनकर ने बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के अप्रशिक्षित होने से आ रही समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर (सर्वे ऑफ इनफिल्ट्रेशन एंड रेजिडेंट्स) की प्रक्रिया को बिना व्यावहारिक समझ के, सीमित समय में तेजी से लागू किया गया है, जिससे लोगों में हलचल और परेशानी है।

उन्होंने जोर दिया कि जनता के बीच यह जानकारी ठीक से पहुंचाई जानी चाहिए कि कौन–कौन से प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। डॉ. सोनकर ने बताया कि 2003 में मतदान करने वाले कई लोगों के नाम आज भी मतदाता सूची में नहीं हैं, जबकि उनके पास वोटर कार्ड और अन्य प्रमाण हैं। इसी तरह, 2024 में वोट देने वालों का 2025 में डेटा उपलब्ध नहीं है। विधायक ने उन महिलाओं की समस्याओं पर भी प्रकाश डाला जो शादी करके दूसरे जनपदों या प्रदेशों से आई हैं। उनके डेटा को एकत्र करने में कठिनाई आ रही है। उन्होंने सरकार से ऐसी महिलाओं की अलग से मदद करने का आग्रह किया।

डॉ. सोनकर ने कहा कि एसआईआर में कितनी बहुओं के नाम काटे गए और कितने जोड़े गए, इससे पता चलेगा कि सरकार महिलाओं की कितनी हितैषी है।

अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर बोलते हुए, डॉ. सोनकर ने कहा कि सबसे पहले भारतीय नागरिकों को पुख्ता प्रमाण देने की जरूरत है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार खुद आधार को कभी वैध नहीं मानती, तो उन गरीबों का क्या होगा जिनके पास आधार के अलावा कोई प्रमाण नहीं है? कहीं उन्हें भी घुसपैठिया कहकर न निकाल दिया जाए।

उन्होंने सरकार से एक ऐसा आईडी कार्ड सुनिश्चित करने की मांग की, जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो सके कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन घुसपैठिया नहीं है। विधायक ने कहा कि सरकार आधार की वैधता तय नहीं कर पाई है, जबकि बड़े–बड़े कार्य आधार नंबर से होते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को खुद पर भरोसा नहीं है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, लखनऊ के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की अध्यक्षता में किया गया

लखनऊ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की इस कार्यशाला में 250 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में डॉ नितेश धवन, राज्य निदेशक , खादी और ग्रामोद्योग आयोग, लखनऊ, श्री उमेश चन्द्र , संयुक्त आयुक्त, उद्योग विभाग, कानपुर, श्री सिद्धार्थ यादव, संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, महाप्रबंधक, संयोजक, एस0एल0बी0सी0 बैंक ऑफ बड़ौदा, उ0प्र0 राज्य के विभिन्न जिलों के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिकारी , उ0प्र0 राज्य के विभिन्न जिलों के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, क्षेत्र से आये विभिन्न जिलों के जिला अग्रणी बैंक अधिकारी तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग, लखनऊ के अन्य कर्मचारी एवं अधिकारी इत्यादि शामिल रहे। श्री शिशिर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा गाँधीजी के चित्र पर पुष्पांजलि देते हुये कार्यक्रम की शुरूआत की गई। श्री शिशिर जी द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की छोटी–छोटी पॉलिसी से सम्बन्धित कमियों को दूर करने हेतु विभिन्न सुझाव देन के लिए आग्रह किया गया । उनके द्वारा वर्ष 2008 से 2025 तक 11 लाख लोगो को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की भूरि–भूरि प्रशंसा की गई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग हर वर्ष 250 करोड़से अधिक की धनराशि प्रतिवर्ष के अनुसार मार्जिन मनी निर्गत की जा रही हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अनु0 जाति/जनजाति के आम नागरिको को हैन्डहोल्डिंग सपोर्ट देकर रोजगार सृजन करने में मदद करने के लिए केवीआईसी, केवीआईबी, जिला ग्रामोद्योग तथा बैंको के अधिकारियों से आग्रह किया। उनके द्वारा यह भी कहा गया की स्टार्ट–अप के दौर में देश की जरूरतों के अनुसार किस

तरह से उपलब्ध स्त्रोत का उपयोग करके देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉ नितेश धवन , राज्य निदेशक , खादी और ग्रामोद्योग आयोग, लखनऊ, उ0प्र0 द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के विषय पर विस्तृत जानकारी दी। डॉ नितेश धवन , राज्य निदेशक , खादी और ग्रामोद्योग आयोग, लखनऊ, उ0प्र0 द्वारा पीपीटी के माध्यम से वर्ष 2024 से तुलनात्मक विवरण करते हुये वर्ष 2025 में सकारात्मक बदलाव के विषय में विस्तृत जानकारी दी |साथ ही श्री आशुतोष कुमार सिंह, सह निदेशक द्वारा भी पीएमईजीपी योजना की विस्तृत जानकारी दी।

श्री उमेश चन्द्र , संयुक्त आयुक्त, उद्योग विभाग, कानपुर द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के विषय में बताया की यह एक फलैक्सी योजना है, जिसका आम जनता को अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। साथ ही केवीआईसी, केवीआईबी, जिला ग्रामोद्योग तथा बैंकों के अधिकारियों से भी आग्रह किया की किस तरह से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना को ज्यादा से ज्यादा लोगो को लाभान्वित कराने का प्रयास करें। श्री सिद्धार्थ यादव, संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के लम्बित प्रस्तावों , भौतिक सत्यापन से सम्बन्धित तथा योजना से जुड़ी किसी भी लम्बित समस्या को जल्द से जल्द निस्तारण करने हेतु आग्रह किया गया। श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, महाप्रबंधक, संयोजक, एस0एल0बी0सी0, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बैको को जल्द टारगेट पूरा करने के लिए बधाई दीया। तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना की लम्बित पड़ेह हुये प्रस्तावो पर जल्द से जल्द निस्तारण के लिए आग्रह किया। साथ ही सैकेण्ड लोन के प्रस्तावों को करने हेतु जोर दिया। कार्यशाला में पीएमईजीपी के सफल उद्यमियों के द्वारा अपनी–अपनी सफलता की कहानी के विषय पर विस्तारपूर्वक बताया गया। इसी के साथ कार्यक्रम में पीएमईजीपी योजना पर खुली चर्चा के दौरान उ0प्र0 राज्य से विभिन्न जनपदों से आये हये जनपद स्तर के पदाधिकारियों द्वारा अपनी–अपनी समस्याओं को रखा , जिसका निस्तारण केवीआईसी के अधिकारियों द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना में उ0प्र0 राज्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक को प्रथम पंजाब नेशनल बैंक को द्वितीय तथा बैंक ऑफ बड़ौदा को तृतीय पुरस्कार से सम्मनित किया गया। साथ ही जनपदो में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए क्रमशः वाराणसी, आजमगढ़ तथा गाजीपुर के जिला अग्रणी बैंक प्रबधकों के प्रबंधको को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार देते हुये सम्मानित किया गया। अंत में श्री के0पी0 , कार्यकारी , सह निदेशक–।। , खादी और ग्रामोद्योग आयोग, वाराणसी द्वारा सभी को धन्यवाद देते हुये कार्यक्रम का समापन किया।

6 दिसंबर की पूर्व संध्या पर व जुमे की नमाज को लेकर सभी मस्जिदों पर रही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

शहरी क्षेत्र मे 110 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 323 मस्जिद किये गये चिन्हित

अयोध्या। 6 दिसंबर की पूर्व संध्या पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट दिखाई दे रही है।इस दिन किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न होने पाए इससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी चेकिंग अभियान करते हुए दिखाई दिए।वही 6 दिसंबर से एक दिन पूर्व शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के समय जिले के सभी मस्जिदों पर पर्याप्त

संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात रहे।शाम को जिले के सभी सर्किल के सीओ अपने–अपने अधीनस्थ संबंधित प्रभारी निरीक्षकों तथा थानाध्यक्षों व पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों के साथ चेकिंग अभियान भी करते हुए दिखाई दिए।सीओ सिटी श्रेयश त्रिपाठी,सीओ अयोध्या आशुतोष त्रिपाठी,सीओ सदर अरविंद सोनकर सहित सभी सीओ खास कर चार पहिया वाहनों का चेकिंग करते हुए संदिग्ध अवस्था में दिखाई देने वाले लोगों से पूछताछ किया। 6 दिसंबर से एक दिन पहले शुक्रवार को सभी मस्जिदों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात रहे इस संबंध में एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 323 मस्जिद स्थित है।बताया कि थाना गोसाईगंज मे 37, थाना महाराजगंज मे 13, थाना रौनाही मे 26,थाना बीकापुर मे 29,थाना तारुन मे 14,थाना हैदरगंज मे 17,थाना इनायत नगर मे 32,थाना कुमारगंज मे 17, खंडासा 8 मे,थाना रुदौली मे 82,थाना पटरंगा मे 15 तथा थाना बाबा बाजार मे 22 मस्जिद है।सुरक्षा की दृष्टि से सभी मस्जिदों पर संबंधित थानों के प्रभारी निरीक्षक तथा चौकी प्रभारी पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों के साथ मौजूद रहेंगे।इसके लिए बाहर से भी कुछ सुरक्षा कर्मी जिले में आए हैं।वहीं सीओ सिटी श्रेयश त्रिपाठी ने बताया कि सर्किल सिटी में कुल 110 मस्जिद हैं।जिसमे थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में 75 तथा कैंट में 35 मस्जिद स्थित है। बताया कि 6 दिसंबर को लेकर सभी मस्जिदों पर विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है और आसपास होने वाली गतिविधियों को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा रही है।

संजय सिंह राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद (रजि.) जौनपुर के जिला अध्यक्ष नियुक्त

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्रा राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद ने

जौनपुर के तेजतर्रार, वरिष्ठ एवं निर्भीक पत्रकार संजय सिंह पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह दैनिक मान्यवर समाचार पत्र से को राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद (रजि.) जौनपुर का जिला अध्यक्ष नियुक्त करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संजय सिंह जी जनपद में संगठन के उत्थान, विस्तार और पत्रकार हितों की रक्षा हेतु निष्ठा, ईमानदारी एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे।संजय सिंह के इस मनोनयन पर उनके शुभ चिंतकों मित्र और पत्रकार साथियों ने बधाई शुभकामनाएं देते उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया है।

मेडिकल कालेज के वार्षिकोत्सव प्रवाह 2025 का पाँचवा दिन–शांति और उत्साह के साथ हुआ सम्पन्न

दैनिक देश की उपासना ब्यूरो
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर के प्रधानाचार्य प्रो० आर०बी० कमल के कुशल नेतृत्व में नोडल वार्षिक उत्सव प्रवाह 2025 डा० मुदित चौहान एवं डा० आदर्श कुमार यादव व डा० पूजा पाठक के द्वारा आज वार्षिक उत्सव के पांचवे दिन शांतिपूर्ण और उत्सवमय वातावरण में सम्पन्न, मेडिकल कॉलेज का वार्षिक उत्सव प्रवाह 2025 अपने पांचवे दिन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। पूरे परिसर में उत्साह, ऊर्जा और रचनात्मकता की अनूठी छाप देखने को मिली। दिन की शुरुवात सौहार्द और अनुशासन से भरे माहौल में हुई, जहाँ छात्रों, शिक्षकों और अतिथियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। विभिन्न शैक्षणिक, खेल सांस्कृतिक आयोजनों ने प्रतिभागियों को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मंच प्रदान किया।

दिनभर चले कार्यक्रम में वॉलीबॉल, लंबी कूद, बैडमिंटन तथा चेस की प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई, जिनमें छात्रों एवं चिकित्सकों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया।

वॉलीबॉल प्रतियोगिता पांचवे दिन की सबसे आकर्षक प्रतियोगिताओं में से एक बॉलीबॉल मैच रहा, जो छात्रों और चिकित्सको के टीमों के बीच खेला गया। रोमांच और शानदार खेल कौशल से भरपूर मुकाबले में चिकित्सकों की टीम विजेता रही। चिकित्सको की टीम की समन्वय क्षमता और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना का केंद्र बना।

बैडमिंटन प्रतियोगिता– बैडमिंटन का मुकाबला डा० जितेन्द्र और डा० नवीन सिंह के बीच खेला गया। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार मुकाबले को अत्यंत प्रतिस्पर्धी बनाया। अंततः बेहतर लय और नियंत्रण को प्रदर्शन करते हुए डा० जितेन्द्र विजेता रहे। चेस प्रतियोगिता– बौद्धिक कौशल और रणनीतिक सोच से भरपूर चेस प्रतियोगिता में मुकाबला प्रो० आशीष यादव और डा० दिग्वेश के बीच हुआ। खेल के हर चरण में रोमांच बना रहा। निर्णायक क्षणों में बेहतर रणनीति अपनाते हुए डा० दिग्वेश विजेता घोषित किए गए। लंबी कूद प्रतियोगिता में एम०बी०बी०एस० पैरा 1 की छात्रा पलक कुमारी ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर विजेता का स्थान प्राप्त किया। उनकी छलांग न केवल प्रतियोगिता की सबसे प्रभावशाली रही, बल्कि दर्शकों से भी खेब प्रशंसा प्राप्त की। पलक कुमारी का यह प्रदर्शन कार्यक्रम की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में शामिल रहा।

पांचवे दिन के समापन अवसर पर प्रधानाचार्य महोदय ने अपने प्रेरणदायी आशीर्वाद वचनों से चिकित्सा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों एव कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि प्रवाह 2025 न केवल खेल एवं सांस्कृतिक प्रतिभाओं का मंच है, बल्कि यह संस्थान की सामूहिक शक्ति, अनुशासन और टीम भावना का प्रतीक है। अन्त में प्रधानाचार्य महोदय ने कहा की सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई देता हूँ । आपका यह उत्साह और समर्पण हमारे संस्थान की गरिमा को बढ़ाता है। आप सभी को उज्ज्वल भविष्य हो यही मेरी शुभकामना है। ज्ञान, सेवा और मानवीय संवेदनाओं के मार्ग पर अग्रसर रहकर आप समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में अवश्य सफल होंगे। प्रधानाचार्य महोदय ने आयोजन समिति, स्वयंसेवकों और सभी योगदानकर्ताओं की सराहना करते हुए आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित की।

इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य प्रो० आशीष यादव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो० ए०ए० जाफरी , डीन रिसर्च प्रो० रुचिरा सेठी, डीन एकेडमिक प्रो० तबस्सुम याशमीन, स्पोर्ट कमेटी अध्यक्ष, प्रो० उमेश कुमार सरोज, प्रो० भारती यादव, प्रो० साधना अजय, डा० विनोद, डा० जितेन्द्र कुमार, डा० अरविन्द पटेल, डा० सी०बी०एस० कर्नल पटेल, डा० अनुज सिंह, डा० सरिता पाण्डेय, डा० राजश्री यादव, डा० स्वाती विश्वकर्मा, डा० अचल सिंह, डा० रोहित कुमार सरोज, डा० चन्द्रभान, डा० आशुतोष सिंह, डा० संजीव यादव, डा० विनोद वर्मा, डा० नवीन सिंह, डा० अर्चना, डा० अनिल कुमार, डा० प्रियंका सिंह, डा० रेनू , डा० अरविन्द यादव, डा० बृजेश कन्नौजिया, डा० अजय, डा० पंकज, डा० जयंत शर्मा, डा० संदीप सिंह, डा० दिग्वेश, डा० मतीन अहमद एवं एम०बी०बी०एस० व पैरामेडिकल छात्र–छात्राएं तथा कर्मचारी उपस्थित रहे।

कोटेदार संघ ने कमीशन वृद्धि के संबंध में जिलापूर्ति अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर कोटेदारों ने ई मशीनें जमा करने की कोशिश की

ब्यूरो प्रमुख/विश्व प्रकाश श्रीवास्तव/ जौनपुर। कोटेदार संघ ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर डी एस ओ को दिया ज्ञापन। हजारों की संख्या में कोटेदारों ने अपने कमीशन में वृद्धि की मांग की। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा और ई–मशीनें जमा करने की कोशिश किया परन्तु जिला पूर्ति अधिकारी ने समझा बुझा कर मशीन नही जमा किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेता (कोटेदार) खाद्यान्न और चीनी पर लाभांश बढ़ाने और

न्यूनतम आय गारंटी की मांग लगातार कर रहे हैं। कोटेदार सरकार के निर्देशों के अनुसार राशन वितरण करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क वितरण किया। इस दौरान ई–पास मशीन से ईमानदारी से वितरण के लिए उनकी सराहना हुई और उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार से प्रशस्ति पत्र भी मिला। कोटेदार आयुष्मान कार्ड, किसान फार्मर रजिस्ट्री और वोटर लिस्ट संशोधन जैसे अन्य सरकारी कार्यों में भी सहयोग करते हैं। हालांकि, उत्तर प्रदेश में कोटेदारों को खाद्यान्न पर केवल 90 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश मिलता है। इसकी तुलना में, हरियाणा में 200 रुपये, गोवा में 220 रुपये, केरल में 200 रुपये और दिल्ली में 200 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश दिया जा रहा है। गुजरात में 20,000 रुपये की न्यूनतम आय गारंटी भी दी जाती है। संघ की मांग है कि अन्य राज्यों की तरह लाभांश और न्यूनतम आय गारंटी प्रदान की जाए, ताकि बढ़ती महंगाई में उनके परिवारों का भरण–पोषण हो सके। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो कोटेदार 28 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी जिला अध्यक्ष हरसू सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष दयाशंकर निगम, महासचिव पद्माकर उपाध्याय महासचिव, सलीमुल्लाह मीडिया प्रभारी, महेंद्र यादव, राकेश मिश्रा, राम सभार यादव, लुकमान ,राकेश, के.के जैसवाल, मनोज जायसवाल, संतोष गुप्ता, अनुज गुप्ता, संतोष ,राधेश्याम, ईश्वर चंद ,अशोक कुमार ,अमरनाथ, संतोष यादव, राकेश मोरिया, अनुराधा मौर्य ,आदिल शेख सहित हजारों कोटेदार मौजूद रहे।

पोको का नया सी85 5 जी स्मार्टफोन 9 दिसंबर को होगा लान्च, पावरफुल बैटरी और 5जी पर फोकस

सिटी रिपोर्टर प्रत्यूष पाण्डेय

लखनऊ। परफॉर्मेंस–केन्द्रित स्मार्टफोन ब्रांड पोको ने आज भारत में अपने नए मॉडल POCO C85 5G के लॉन्च की घोषणा की। यह कंपनी की 2025 लाइन–अप का अंतिम मॉडल है और C–सीरीज में एक महत्वपूर्ण विस्तार माना जा रहा है। भारत के युवा और डिजिटल–फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया यह स्मार्टफोन भरोसेमंद पावर, दमदार प्रदर्शन और लंबी बैटरी लाइफ प्रदान करता है–वह भी एक ऐसे डिजाइन के साथ जिसे उपयोगकर्ता आत्मविश्वास से प्रदर्शित कर सकें।

बैटरी तकनीक हमेशा से POCO की सबसे बड़ी ताकत रही है। आज जब उपभोक्ता स्मार्टफोन में ज्यादा बैटरी बैकअप, तेज चार्जिंग और स्लिम डिजाइन चाहते हैं, POCO इन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए बाजार में अपनी बढ़त बनाए हुए है। इस वर्ष लॉन्च हुए F7, X7 सीरीज और M7 प्लस जैसे मॉडलों के साथ कंपनी ने बैटरी परफॉर्मेंस के नए मापदंड तय किए हैं। POCO C85 5G भी इन्हीं मानकों को आगे बढ़ाता है और बेहतर बैटरी अनुभव का दावा करता है।

POCO C85 5G को विशेष रूप से रोजमर्रा के उपयोग और युवा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन किया गया है। इसमें आकर्षक डुअल–टोन फिनिश, पतला प्रोफाइल और भरोसेमंद परफॉर्मेंस पर विशेष ध्यान दिया गया है। 6000mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग के साथ यह डिवाइस निर्बाध प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। सामान्य उपयोग में इसकी बैटरी दो दिनों से अधिक चल सकती है, जिससे उपयोगकर्ताओं को बार–बार चार्जिंग की चिंता नहीं रहती।

POCO C85 5G की पहली झलक आज कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी की गई। यह स्मार्टफोन मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 को भारत में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी मे. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार-पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।